एच.एस.बी.

पूर्ण बेंच

लेटर्स पेटेंट अपील

कार्यवाहक माननीय मुख्य न्यायाधीश *ओ चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति एमआर शर्मा और सुरिंदर सिंह,* के समक्ष ।

हरियाणा राज्य और अन्य, अपीलकर्ता।

बनाम

श्री राम चन्दर - *प्रतिवादी।*

1975 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 20

2 अगस्त, 1976

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (*1872* का 1) - *सुनी-सुनाई बात साक्ष्य - जब घरेलू न्यायाधिकरणों के समक्ष स्वीकार्य हो - जांच अधिकारी किसी अपराधी के आचरण पर विस्तृत रिपोर्ट दे रहा हो - अनुशासनात्मक प्राधिकरण ऐसी रिपोर्ट से सहमत हो और जुर्माना लगा रहा हो - ऐसा प्राधिकारी - चाहे वह कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य हो।*

यह सच है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा अनुमत सीमा के अलावा कानून की अदालतों में सुनी-सुनाई गवाही स्वीकार्य नहीं है। लेकिन, साक्ष्य का यह सख्त नियम घरेलू न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। सुनी-सुनाई बात साक्ष्य "तार्किक रूप से प्रोबेटिव" है, हालांकि किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार इसका प्रोबेटिव मूल्य मजबूत या कमजोर हो सकता है। यदि यह "तार्किक रूप से प्रोबेटिव" है, तो एक

न्यायाधिकरण इस पर कार्रवाई करने का हकदार है। इस प्रकार, जबकि घरेलू न्यायाधिकरणों द्वारा सुनी-सुनाई बातों के स्वागत के खिलाफ कोई रोक नहीं है, इस तरह के सबूत किस हद तक प्राप्त और उपयोग किए जा सकते हैं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए।

(पैरा 3 और 4)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां नियमों के तहत अपराधी के अपराध की विस्तृत जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जहां जांच अधिकारी अपने निष्कर्षों और अपने निष्कर्षों के कारणों को देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर सहमत होता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्रत्येक मामले में कारण दर्ज करने के लिए बाध्य है। एक ऐसे मामले के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होता है और एक मामले में जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होता है। पूर्व में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए कारणों को रिकॉर्ड करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है, जबकि बाद के मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है। इस प्रकार, जहां एक जांच अधिकारी ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार करता है और जुर्माना लगाता है, तो बाद में इसके कारणों को रिकॉर्ड करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है।

(पैरा 6 और 8)

12 अगस्त,1975 को माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री आरएस नरूला और माननीय न्यायमूर्ति के. एस. तिवाना की खंडपीठ द्वारा *मामले को कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय के लिए पूर्ण पीठ को सौंप दिया गया। पूर्ण पीठ* जिसमें *माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री* ओ. *चिन्नप्पा रेड्डी, माननीय न्यायमूर्ति* श्री *एमआर शर्मा और माननीय न्यायमूर्ति* श्री *सुरिंदर सिंह* थे, *ने अंततः 2 अगस्त,* 1976 को मामले का फैसला किया।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंन्द्र नाथ मित्तल द्वारा 25 नवम्बर, 1974 को दिए गए निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के *अंतर्गत* लेटर्स पेटेंट अपील की 1973 की सिविल रिट नंबर 401 में।

अपीलकर्ताओं की ओर से एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) श्री सी.डी.दीवान और श्री नौबत सिंह, ए.ए.जी., (हरियाणा) *उपस्थित थे।*

प्रतिवादी की ओर *से श्री यू.एस.साहनी, अधिवक्ता।*

निर्णय

ओ. चिन्नप्पा रेड्डी, ए.सी.जे. (1) - इस मामले को नरूला, सीजे और तिवाना, जे. द्वारा पूर्ण पीठ को भेजा गया है, जैसा सोचा गया था कि तरलोचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1) मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ की टिप्पणियाँ बहुत व्यापक थीं और उस मामले में निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी। प्रतिवादी हरियाणा रोडवेज, रोहतक में कंडक्टर था। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच हुई थी। दो आरोप लगाए गए थे। पहला यह था कि 21 मई, 1970 को जब वह बस संख्या 1346 पर ड्यूटी पर थे, तो वह उन चालीस यात्रियों को टिकट जारी करने में विफल रहे, जिनसे उन्होंने पूरा किराया वसूला था और उन्होंने इस तरह एकत्र की गई राशि का गबन किया था। दूसरा आरोप यह था कि जब उसकी जांच की गई तो उसने अपनी

जेब में विभिन्न मूल्यवर्ग के टिकटों को पंच किया था। पहले आरोप के संबंध में उनका बचाव यह था कि रेवाड़ी में बड़ी संख्या में यात्री बस में सवार हो गए थे और जब वह यात्रियों को जितनी जल्दी हो सके टिकट जारी कर रहे थे, बस को जांच के लिए केंद्रीय फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा टंकरी गांव में रोक दिया गया था। उसने चेकर्स को बताया कि बस ओवरलोडेड थी, कि उसने यात्रियों से किराया नहीं लिया था और उसने अभी तक टिकट जारी नहीं किया था। यह कहना गलत था कि उन्होंने यात्रियों से किराया वसूला था। दूसरे आरोप के संबंध में, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके पास से कोई पंच टिकट बरामद किया गया था। जांच अधिकारी के समक्ष, प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए दो चेकर्स से पूछताछ की गई थी। हालांकि, किसी भी यात्री की जांच नहीं की गई। दो चेकर्स ने बस की जांच करने और बिना टिकट के चालीस यात्रियों को खोजने के लिए गवाही दी।

(1) 1975 वर्ष एल.जे. 1,

उन्होंने कहा कि यात्रियों ने उन्हें बताया कि कंडक्टर ने उनसे पूरा किराया वसूला है। उन्होंने कंडक्टर की जेब से कुछ पंच किए गए टिकटो की बरामदगी के बारे में भी बताया। कंडक्टर ने बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सोम नाथ से पूछताछ की। सोम नाथ ने कहा कि यात्रियों की भीड़ थी और उनमें से कई के पास कोई टिकट नहीं था। जांच अधिकारी ने प्रतिवादी को दोनों आरोपों का दोषी पाया और अपनी रिपोर्ट महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज को सौंप दी। उत्तरार्द्ध ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उस पर सेवा की समाप्ति का जुर्माना क्यों न लगाया जाए। प्रतिवादी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक

ने 17 फरवरी, 1971 को प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित किया। प्रतिवादी ने राज्य परिवहन नियंत्रक, हरियाणा के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। अपील खारिज कर दी गई थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया। हमारे विद्वान भाई आर. एन. मित्तल, जे. ने दो आधारों पर सिविल रिट याचिका की अनुमति दी। पहला आधार यह था कि जांच अधिकारी के समक्ष कोई कानूनी सबूत नहीं था क्योंकि किसी भी यात्री से पूछताछ नहीं की गई थी और यात्रियों ने उन्हें जो बताया उसके बारे में चेकर्स के साक्ष्य सुनी-सुनाई बातें थीं और इसलिए, साक्ष्य में अस्वीकार्य थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने *तरलोचन सिंह के मामले* (सुप्रा) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया। दूसरा आधार जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने रिट याचिका की अनुमति दी, वह यह था कि सेवा कि सेवा समाप्ति का आदेश गूढ़ था न कि मौखिक आदेश। हरियाणा राज्य ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

(2) विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या यात्रियों द्वारा उन्हें जो बताया गया था उसके बारे में चेकर्स का साक्ष्य प्रतिवादी के खिलाफ घरेलू जांच में कानूनी सबूत नहीं था। उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार यह दोहराया गया है कि सांविधिक मार्गदर्शन के अभाव में घरेलू न्यायाधिकरणों को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है और वे साक्ष्य के सख्त नियमों से भी बाध्य नहीं हैं। प्रक्रिया के नियम और न्यायालयों में देखे गए साक्ष्य के नियम अक्सर घरेलू पूछताछ में गलत होते हैं। एक घरेलू न्यायाधिकरण, जिसकी प्रक्रिया एक क़ानून द्वारा विनियमित नहीं है, अपनी स्वयं की प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वतंत्र है जब तक कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह किसी भी स्रोत से सबूत प्राप्त करने के लिए समान रूप से स्वतंत्र है यदि यह "तार्किक रूप से

प्रोबेटिव" है। मैसूर राज्य बनाम शिवबसप्पा में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि -

"अर्ध-न्यायिक कार्यों का उपयोग करने वाले घरेलू न्यायाधिकरण अदालतें नहीं हैं और इसलिए, वे अदालतों में कार्रवाई के परीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं और न ही वे साक्ष्य के सख्त नियमों से बंधे हैं। वे अदालतों के विपरीत, सभी स्रोतों से और सभी चैनलों के माध्यम से जांच के तहत बिंदुओं के लिए सभी जानकारी, सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, बिना उन नियमों और प्रक्रियाओं से बंधे जो अदालत में कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। कानून उन पर एकमात्र दायित्व डालता है कि उन्हें प्राप्त होने वाली किसी भी जानकारी पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे इसे उस पार्टी को नहीं डालते हैं जिसके खिलाफ इसका उपयोग किया जाना है और उसे इसे समझाने का उचित अवसर दें। उचित अवसर क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन जहां ऐसा अवसर दिया गया है, वहां कार्यवाही इस आधार पर हमले के लिए खुली नहीं है कि जांच अदालतों में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी।

इन टिप्पणियों को के. एल. शिंदे बनाम मैसूर राज्य (3) में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। बाद के मामले में यह माना गया कि घरेलू पूछताछ में मुकरने वाले गवाहों के पिछले बयान अपराधी के खिलाफ साक्ष्य में स्वीकार्य थे। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की -

> "यह भी देखा जा सकता है कि विभागीय कार्यवाही आपराधिक अभियोजन के समान नहीं होती है जिसमें उच्च स्तर के सबूत की आवश्यकता होती है। यह सच है कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा अक्की सहित तीन पुलिस

कांस्टेबलों द्वारा दिए गए पहले के बयानों पर भरोसा किया गया था, जिससे वे पलट गए थे। लेकिन उन्होंने जांच या बर्खास्तगी के आदेश को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि विभागीय कार्यवाही साक्ष्य अधिनियम में निहित साक्ष्य के सख्त नियमों द्वारा शासित नहीं होती है।

(3) सुनी-सुनाई बातें फिप्सन द्वारा अपने 'साक्ष्य के नियम' में देखी गई निम्नलिखित कमजोरियों से ग्रस्त हो सकती हैं: (1) मूल घोषणाकर्ता की गैरजिम्मेदारी, जिसके बयान न तो शपथ पर दिए गए थे, न ही जिरह के अधीन थे; (2) पुनरावृत्ति की प्रक्रिया में सत्य का मूल्यह्रास और (3) धोखाधड़ी के अवसर, इसके प्रवेश से खुलेंगे; जिसमें कभी-कभी जोड़ा जाता है (4) कानूनी जांच के लिए ऐसे सबूतों की प्रवृत्ति, और (5) मजबूत सबूतों के लिए कमजोर के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए।

इन दुर्बलताओं के बावजूद फिप्सन ने माना कि इस तरह के सबूतों को अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुनी-सुनाई बातों में विश्वास को अक्सर सहज माना जाता था; सभी घटनाओं में यह अनुभव द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत था, क्योंकि दुनिया के व्यापार का नौ-दसवां हिस्सा इसके आधार पर आयोजित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि नियम की छूट को कानून द्वारा लगातार मंजूरी दी गई थी।

(2) ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 375.

(3) 1976 (3) एस.सी.सी. 76.

हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि इंग्लैंड में हाल ही में क़ानून

द्वारा काफी हस्तक्षेप किया गया है और पहली बार सुनी गई बात अब कानून की अदालतों में साक्ष्य में स्वीकार्य है। भारत में भी, सुनी-सुनाई बातों का बहिष्कार कभी भी पूर्ण नियम में नहीं रहा है। यहां तक कि अदालतों में भी सुनी-सुनाई बातों के नियम के अपवाद हमेशा रहे हैं। वास्तव में मरने से पहले दिए गए बयानों और वापस लिए गए बयानों से काफी संभावित मूल्य जुड़े होते हैं, जो सुनी-सुनाई बातों के अलावा और कुछ नहीं बल्कि सुने गए साक्ष्य होते हैं। यह सच है कि कानून की अदालतों में साक्ष्य अधिनियम द्वारा अनुमत सीमा को छोड़कर सुने हुए साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हैं। लेकिन, ऐसा कोई कारण नहीं है कि साक्ष्य के इस सख्त नियम को घरेलू न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही पर लागू किया जाना चाहिए। सुनी-सुनाई बात साक्ष्य "तार्किक रूप से प्रोबेटिव" है, हालांकि किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार इसका प्रोबेटिव मूल्य मजबूत या कमजोर हो सकता है। यदि यह "तार्किक रूप से प्रोबेटिव" है, तो एक न्यायाधिकरण इस पर कार्रवाई करने का हकदार है। टी *ए मिलर* लिमिटेड बनाम *आवास और स्थानीय सरकार मंत्री और एक अन्य (4) में लॉर्ड डेनिंग, एम.आर. की निम्नलिखित टिप्पणियां उपयुक्त* हैं और इस बिंदु के लिए बहुत उपयुक्त हैं: -

> "इस तरह का एक न्यायाधिकरण अपनी प्रक्रिया का स्वामी है, बशर्ते कि प्राकृतिक न्याय के नियम लागू हों। अधिकांश यहां साक्ष्य शपथ पर थे, लेकिन यही कारण है कि सुनी-सुनाई बातों को वहां स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जहां इसे काफी हद तक विश्वसनीय माना जा सकता है।

(4) (1968) 1 साप्ताहिक कानून रिपोर्ट, 492,

ट्रिब्यूनल किसी भी सामग्री पर कार्रवाई करने के हकदार हैं जो तार्किक रूप से प्रोबेटिव है, भले ही यह कानून की अदालत में सबूत न हो; देखें रेग बनाम उप औद्योगिक चोट आयुक्त, एकपक्षीय, मूर ।(5) संसद में इसी सप्ताह के दौरान हमने सिविल साक्ष्य विधेयक का दूसरा वाचन किया है। यह सुनी-सुनाई बातों के खिलाफ नियम को समाप्त करता है, यहां तक कि देश की सामान्य अदालतों में भी। यह सुरक्षा उपायों के अधीन सिविल कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से सुनी सुनाई बातों को स्वीकार करने की अनुमति देता है। *सुनी-सुनाई बातें न्यायाधिकरण के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार्य हैं।* यह स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं है, ट्रिब्यूनल को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे जिरह द्वारा परीक्षण किया जाए। इसका मतलब केवल यह है कि ट्रिब्यूनल को दूसरे पक्ष को इस पर सहमत होने और इसका खंडन करने का उचित अवसर देना चाहिए: देखें *शिक्षा बोर्ड* बनाम *चावल* (6), रेग बनाम उप औद्योगिक चोट आयुक्त"।

(4) *इसलिए, हमारा विचार है कि घरेलू न्यायाधिकरणों द्वारा सुनी-सुनाई बातों को स्वीकार करने के खिलाफ कोई रोक नहीं है, लेकिन इस तरह के साक्ष्य किस हद तक प्राप्त और उपयोग किए जा सकते हैं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्राकृतिक न्याय के*

सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने जगन्नाथ प्रसाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (7) *मामले* में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। जहां सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों और उत्तर प्रदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही (प्रशासनिक न्यायाधिकरण) नियमों की तुलना की और निम्नानुसार देखा: -

> पीठ ने कहा, "जांच के दो रूपों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। जांच अपने वास्तविक स्वरूप में अर्ध-न्यायिक है। जांच की प्रकृति से ही यह स्पष्ट है कि पूछताछ करने वाले निकाय के समक्ष रखी गई सामग्री के प्रति दृष्टिकोण न्यायिक होना चाहिए। यह विनियम 490 द्वारा सच है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन ट्रिब्यूनल नियमों के नियम 8 के तहत भी, ट्रिब्यूनल को इक्विटी और प्राकृतिक न्याय के नियमों द्वारा निर्देशित किया जाना है और साक्ष्य से संबंधित प्रक्रिया के औपचारिक नियमों से बाध्य नहीं है। यह आग्रह किया गया था कि जबकि ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड पर साक्ष्य स्वीकार कर सकता है जो सुनी-सुनाई बात है, पुलिस विनियमों के तहत मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए और सुनी-सुनाई बातों को बाहर रखा जाना चाहिए।

(5) (1965) 1 प्र.बी. 465.

(6) (1911) ए.सी. 179.

(7) ए.आई.आर., 1961 एस.सी., 1245,

हमें नहीं लगता कि इस तरह के किसी भेद का इरादा था। भले ही ट्रिब्यूनल प्रक्रिया और साक्ष्य से संबंधित औपचारिक नियमों से बाध्य नहीं है, लेकिन यह *सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकता है जो विशुद्ध रूप से सुनी-सुनाई बात है,* क्योंकि इस प्रकृति की जांच में ऐसा करना समानता और 'प्राकृतिक न्याय' के नियमों के विपरीत होगा।

प्रतिवादी के वकील चाहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को पढ़ें, क्योंकि यह कहना कि सुनी-सुनाई बातें घरेलू जांच में भी पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। हमें नहीं लगता कि हम उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को पढ़ सकते हैं। हमारे द्वारा जोर देने के लिए रेखांकित वाक्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनी-सुनाई बातों की सामान्य अविश्वसनीयता और शुद्ध सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करने में शामिल प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन पर जोर दे रहा था। हम स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं: यदि आधा दर्जन व्यक्ति हरियाणा रोडवेज के कार्यालय में जाते हैं और शिकायत करते हैं कि एक निश्चित बस के कंडक्टर ने उनसे किराया वसूला लेकिन उन्हें टिकट जारी नहीं किया और यदि बाद में यात्रियों से पूछताछ नहीं की जाती है तो केवल यात्रियों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अपराध का पता लगाया जाएगा। यह शुद्ध सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है और इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन शामिल है। दूसरी ओर, जहां एक बस की जांच की जाती है और यह पाया जाता है कि कई यात्रियों को टिकट जारी

नहीं किए गए हैं और यात्री कंडक्टर की उपस्थिति में कहते हैं कि उन्होंने किराया चुकाया है, जांच अधिकारी इन तथ्यों को बताने वाले चेकर्स के सबूतों पर कार्रवाई करने में उचित होगा, भले ही यात्रियों से स्वयं गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई हो। उनके द्वारा प्राप्त अपराध का निष्कर्ष शुद्ध सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं होगा। यह (1) चेकर के साक्ष्य कि उसने यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया और (2) यात्रियों द्वारा चेकिंग के समय चेकर को दिए गए बयान पर आधारित होगा। केवल साक्ष्य का दूसरा विषय सुनी-सुनाई बात होगी, लेकिन यह उच्च प्रमाणात्मक मूल्य की सुनी-सुनाई बात होगी क्योंकि परिस्थिति यह है कि बयान कंडक्टर की उपस्थिति में और मौके पर दिए गए थे। ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष अविश्वसनीय प्रकृति की शुद्ध सुनी-सुनाई बातों या सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं। इसलिए, हमें नहीं लगता कि *जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के मामले* में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रतिवादी के विद्वान वकील के तर्क का समर्थन करता है। यह निर्णय किसी भी तरह से हमारे द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के साथ असंगत नहीं है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें हम *तरलोचन सिंह के मामले में टिप्पणियों को खारिज करते हैं।*

(5) विचारणार्थ अगला प्रश्न यह है कि क्या सेवा समाप्ति के आदेश का इस आधार पर उल्लंघन किया गया है कि यह बोलने का आदेश नहीं है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट आरोपों, साक्ष्यों, निष्कर्षों

और निष्कर्षों के कारणों को संदर्भित करती है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। प्रतिवादी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, महाप्रबंधक ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

> ""मैंने जांच कार्यालय की रिपोर्ट, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और श्री राम चंदर सी/9 द्वारा उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब को सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है - नंबर 338/ईए, दिनांक 1 फरवरी, 1971 । उसके द्वारा की गई 42.78 रुपये की धोखाधड़ी का मामला पूरी तरह से स्थापित है। उसके पास से पुराने इस्तेमाल किए गए टिकटों की बरामदगी भी उसके गलत इरादे को साबित करती है। इसलिए मैं 17 फरवरी, 1971 से उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश देता हूं।
>
> (6) विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह आदेश कानून की अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही, जहां तक यह उसके अपराध के निर्धारण से संबंधित है, प्रकृति में अर्ध-न्यायिक थी और इसलिए, यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कर्तव्य था कि वह कारणों सहित अपने आदेश का समर्थन करे।

(8) ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 364.

यह सच है, जैसा कि भारत संघ बनाम *एच. सी. गोयल* (8) *में उल्लेख किया गया* कि यद्यपि कदाचार के दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जा सकता है, इसे प्रशासनिक आदेश के रूप में वर्णित किया जा सकता है, फिर भी, ऐसे लोक सेवक के खिलाफ वैधानिक नियमों के तहत की गई कार्यवाही यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी है, अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति में है। लेकिन, इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मामले में बर्खास्तगी के आदेश को आवश्यक रूप से कारणों से समर्थित किया जाना चाहिए। जहां नियमों के तहत अपराधी के अपराध की विस्तृत जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जहां वह जांच अधिकारी अपने निष्कर्षों और अपने निष्कर्षों के कारणों को देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होता है, तो यह कानून के मामले के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण प्रत्येक मामले में कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है। एक ऐसे मामले के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होता है और उन पर कार्य करता है और एक ऐसा मामला जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होता है। पूर्व

में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए हमेशा कारणों को रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं होता है, जबकि बाद के मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए ऐसा करना आवश्यक है। दो प्रकार के मामलों के बीच अंतर को गजेन्द्रगडकर, सीजे द्वारा मद्रास *राज्य बनाम ए. आर. श्रीनिवासन* (9) *मामले* में उजागर किया गया है। जहां उन्होंने निम्नानुसार अवलोकन किया: -

"इस प्रश्न से निपटने में कि क्या दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाने के आदेश के समर्थन में कारण बताना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही उस संबंध में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई जांच से शुरू होती है। उस जांच के बाद एक रिपोर्ट आती है और जहां आवश्यक होता है वहां लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई सामग्री और जो चूककर्ता अधिकारी को भी उपलब्ध कराई गई है, के संबंध में, हमें यह सुझाव देना कुछ हद तक अनुचित लगता है कि राज्य सरकार को अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए कि वह अधिकरण के निष्कर्षों को क्यों स्वीकार करती है। यह विचारणीय है कि यदि राज्य सरकार अधिकरण के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करती है जो दोषी अधिकारी के पक्ष में हो सकते हैं और दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करते हैं, तो उसे कारण बताना चाहिए कि यह ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों से अलग क्यों है, हालांकि ऐसे मामले में भी, यह

आवश्यक नहीं है कि कारण विस्तृत या विस्तृत होने चाहिए।

(9) ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1827

लेकिन, जहां राज्य सरकार अधिकरण के निष्कर्षों से सहमत है जो अपराधी के खिलाफ हैं महोदय, हमें नहीं लगता कि कानून के मामले के रूप में, यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अधिकरण के निष्कर्षों के अनुसार दोषी अधिकारी के विरुद्ध दंड नहीं लगा सकती है जब तक कि वह यह दिखाने का कारण न दे कि उक्त निष्कर्षों को उसके द्वारा क्यों स्वीकार किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यवाही अर्ध-न्यायिक है; लेकिन जिस तरीके से ये जांच की जाती है, उसे देखते हुए, हमें नहीं लगता कि प्रत्येक मामले में कारणों को दर्ज करने के लिए राज्य सरकार पर कोई दायित्व डाला जा सकता है।"

(7) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने बख्तावर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य *आदि* (10) *मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया,* जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य, आदि बनाम बख्तावर सिंह और अन्य (11) *में* पुष्टि की गई थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें बिजली बोर्ड के दो सदस्यों को पंजाब राज्य द्वारा नोटिस दिया गया था जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि उन्हें क्यों बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनमें से एक बख्तावर सिंह की बर्खास्तगी रद्द की

जा सकती है क्योंकि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था, जिसके लिए सरकार ने उसे दोषी पाया था। अन्य सदस्य राजिंदर पाल अबरोल के संबंध में, यह माना गया कि उनके खिलाफ पारित आदेश एक मौखिक आदेश नहीं था क्योंकि यह यह नहीं दिखाता था कि राजिंदर पाल अबरोल के खिलाफ क्या आरोप स्थापित किए गए थे और मूल रूप से मनमाना था। आदेश निम्नानुसार था: -

उन्होंने कहा, "मैंने श्री आरपी अबरोल द्वारा लगाए गए आरोपों और स्पष्टीकरण का अध्ययन किया है। फाइल पर मौजूद सामग्री से, मेरी निश्चित रूप से राय है कि वह बिजली बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में बनाए रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए, मैं आदेश देता हूं कि श्री अबरोल को विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के उप-खंड (iv) के तहत सदस्यता से हटाया जा सकता है।

आदेश की खामियां स्पष्ट हैं- मंत्री जी द्वारा अपराध का एक भी निष्कर्ष दर्ज किया गया है। आदेश के अवलोकन से, उन आरोपों का पता लगाना संभव नहीं है जिनके लिए आरपी अबरोल को दोषी माना गया था। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारे समक्ष मामले की तरह किसी जांच अधिकारी द्वारा कोई पूर्ण जांच नहीं की गई। मंत्री द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष इस मामले में दर्ज किए गए सबसे पहले निष्कर्ष थे और इसलिए, कोई भी मंत्री से

मौखिक आदेश की उम्मीद कर सकता है।

(10) ए.आई.आर. 1971 पी.बी. & हरियाणा 220

(11) ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 2083

जहां एक जांच अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच की जाती है और कारणों से समर्थित निष्कर्षों को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है, वहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्षों और कारणों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब वह उनसे सहमत हो। ए. आर. श्रीनिवासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था।

(8)प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आर. एस. नरूला, जे. (जैसा कि वह तब थे) *विजय सिंह यादव* बनाम *हरियाणा का राज्य* (12) के फैसले पर भरोसा किया। आर. एस. नरूला, जे., बख्तावर सिंह के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए कथित तौर *पर/ हम* पहले ही उस मामले पर चर्चा कर चुके हैं और इसलिए हम विजय सिंह यादव के मामले पर आगे चर्चा करना जरूरी नहीं समझते हैं/ तथापि, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि *ए आर श्रीनिवासन के मामले को आर* एस नरूला, जे नरूला के ध्यान में नहीं लाया गया था। *ए. आर. श्रीनिवासन के मामले के अधिकार पर,* हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए उनके कारणों को दर्ज करना आवश्यक नहीं था क्योंकि वह जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को स्वीकार कर रहे थे।

(9)प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दो और आधार उठाए, जिन पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि आदेश बर्खास्तगी का था और इसलिए, महाप्रबंधक, आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे। निवेदन बिना किसी आधार के है। महाप्रबंधक द्वारा पारित आदेश सेवा समाप्ति का था और हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत, सेवा की समाप्ति का जुर्माना लगाने के लिए सक्षम

---

(12) 1971 (1) एसएलआर 720।

प्राधिकारी महाप्रबंधक है। विद्वान वकील द्वारा उठाया गया दूसरा आधार यह था कि अपीलीय प्राधिकरण ने प्रतिवादी को व्यक्तिगत सुनवाई नहीं दी। नियमों में व्यक्तिगत सुनवाई का प्रावधान नहीं है और प्राकृतिक न्याय का कोई सिद्धांत नहीं है जिसके लिए आवश्यक है कि इस तरह के मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई की जानी चाहिए।

(10) परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और सिविल रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एम. आर. शर्मा, जे. मैं सहमत हूं।

सुरिंदर सिंह, जे-मैं सहमत हूं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा

---

(12) 1971 (1) एसएलआर 720।